this would mean that funds available with the rural branches of public sector banks for credit deployment will in effect be deployed as such in the rural areas.

(c) and (d). Information reating to District-wise distribution of deposits and advances of scheduled commercial banks, available as at the end of June 1976, is set out in Statement I laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1310/77].

Statewise distribution of deposits and advances of rural and semi-urban offices of Scheduled Commercial Banks available as at the end of December, 1975 is set out in Statement II laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1310/77].

स्ट्रा प्रोडक्टस लिमिटेड तथा जे० के० इन्डस्ट्रीज द्वारा आय-कर का भुगतान

3260. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्षवार स्ट्रा प्रोडक्टस लिमिटेड और जे० के० इंडस्ट्रीज ने कितना आयकर दिया तथा उनसे अभी कितना-कितना आयकर वसूल किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : मैसर्स जे० के० इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के तीन वित्तीय वर्षों में कोई आयकर अदा नहीं किया है ।

वित्तीय वर्ष 1974–75 के दौरान मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्टस लिमिटेड द्वारा कोई आयकर अदा नहीं किया गया । इस कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 1975–76 और 1976–77 के दौरान अदा की गई आयकर की रकम क्रमश: 3 लाख 8 हजार रुपये और 136 लाख 83 हजार रुपये थी ।

30 सितम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार, उक्त दोनों कम्पनियों में से किसी की भी तरफ आयकर की कोई रकम बकाया नहीं थी ।

Economic Assistance from United States

3261. SHRI M. KALYANASUNDARAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether India has made any efforts recently to seek economic assistance from the United States; and

(b) if so, the details thereof and with what results?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). The U. S. Administration has initiated discusssions on the prospects of a resumption of development assistance to India. The areas and projects for which such aid could be utilised are under discussion.

महाराष्ट्र में चीनी मिलों की ओर से मांग पत्र

3262. **श्री केशव राव धोंडगे** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की ओर से केन्द्रीय सरकार को कोई मांग पत्र पेश किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) महाराष्ट्र के सहकारी चीनी कारखानों की ओर से केन्द्रीय सरकार को कोई मांग पत्र नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।